Nandani Creation Limited

(A NSE Listed Company)

JAIPUR KURTI | AMAIVA BY JAIPUR KURTI | Desi Fusion

SYMBOL: JAIPURKURT
ISIN: INE696V01013

To,
The Manager-Listing Department,
The National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, NSE Building,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai-400 051

Dated: 27.10.2022

Subject: Intimation of Newspaper Advertisement of Extract of Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the 2nd Quarter & Half year ended 30th September, 2022.

Reference No: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir,

With reference to the captioned subject and pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper in which the Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the 2nd Quarter & Half year ended 30th September, 2022 have been published:

- English National Daily Newspaper- **"Financial Express"** (All India Edition) dated **Thursday, 27th October, 2022;**
- Hindi (Vernacular) daily Newspaper- "**Nafa Nuksaan**" (Rajasthan Edition) dated **Thursday, 27th October, 2022;**

This is for your information and records.

Thanking You,
FOR NANDANI CREATION LIMITED

GUNJAN JAIN
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
M No.: A45068

एंट्री-लेवल व्हीकल्स को बेचना हो रहा मुश्किल

जयपुर/ऑटो डेस्क

देशभर में छोटे शहरों में ऑटोमोबाइल शोरूमों पर एंट्री-लेवल कार व टू-व्हीलर्स का अनसोल्ड स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि इन व्हीकल्स के लिए डिमांड बेहद कमजोर बनी हुई है। हालात यह हैं कि इन व्हीकल्स को बेचने के लिए कंपनियों को डिस्काउंट व ऑफर्स लांच करने पड़ रहे हैं। गौरतलब है कि कोविड के बाद ऑटोमोबाइल मार्केट में डिस्काउंट व ऑफर्स कंपनियों ने एक तरह से बंद कर दिए हैं।

इंडिया के एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल सेगमेंट में लीडर हीरो मोटोकॉर्प को एचएफ डीलक्स व एचएफ 100 जैसे प्रोडक्ट्स के लिए बॉयर्स को एट्रेक्ट करने के लिए कैश डिस्काउंट व एट्रेक्टिव फाइनेंसिंग ऑफर लांच करने पर मजबूर होना पड़ा है। इस सेगमेंट में कंपनी के लिए उत्तरप्रदेश, राजस्थान व मध्यप्रदेश प्रमुख मार्केट हैं। कंपनी के एक डीलर की मानें तो एंट्री-लेवल सेगमेंट में कस्टमर्स के लिए एफोर्डेबिलिटी इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि यदि कोई



कस्टमर व्हीकल खरीदना भी चाहता है तो वह उसकी Cost of Acquisition व Cost of Operation को देखकर पीछे हट जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूरल व सेमी-अर्बन एरिया में लोगों के लिए टू-व्हीलर देखा जाए तो Shared से Personal Mobility पर शिफ्ट होने का एकमात्र जरिया है। एंट्री-लेवल टू-व्हीलर्स के लिए कस्टमर सेगमेंट में प्रमुख रूप से स्टूडेंट्स, छोटे कारोबारी, ट्रेडर्स व ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है जो काम पर जाने के लिए व्हीकल चाहते हैं। चूंकि फूड-इंफ्लेशन काफी बढ़ गया है, ऐसे में उक्त कस्टमर सेगमेंट ने नया व्हीकल खरीदने की योजनाओं को टालना शुरू कर दिया है। यह ऐसा कस्टमर सेगमेंट है जो फिलहाल मार्केट से गायब है।

उल्लेखनीय है कि सितंबर 2022 में स्कूटर्स व 125सीसी व इससे अधिक इंजन कैपेसिटी वाले टू-व्हीलर्स में मजबूत पोजिशनिंग के चलते हीरो मोटोकॉर्प को पीछे छोड़ होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर्स देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी बनकर उभरी थी। होंडा के एक डीलर का कहना है कि 125सीसी व इससे अधिक की व्हीकल कैटेगरी में डिमांड की कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में डिमांड केवल प्रीमियम व्हीकल्स के लिए ही आ रही है।

कार सेगमेंट में भी यही ट्रेंड बना हुआ है। 5 लाख रुपए तक व 5 से 10 लाख रुपए तक की प्राइस-रेंज वाले मिनी एवं कांपेक्ट कारों का सेल्स वॉल्यूम 2018-19 के मुकाबले सितंबर 2022 क्वार्टर में क्रमश: 44% व 9% घटा है। 5 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों का कुल कार सेल्स में शेयर मात्र 7% रह गया है जबकि वर्ष 2019 में यह 22% था। वहीं 10-15 लाख रुपए व 15-20 लाख रुपए वाले प्राइस-सेगमेंट की कारों का कुल कार सेल्स में शेयर 2019 में क्रमश: 12% व 5% से बढ़कर 21% व 11% पर पहुंच गया है। सियाम डाटा के अनुसार 110सीसी व इससे कम कैपेसिटी वाली कैटेगरीज में मोटरसाइकिल सेल्स वॉल्यूम 2018-19 के मुकाबले सितंबर 2022 क्वार्टर में 35% घटा है।

गौरतलब है कि पिछले 4 वर्ष में एंट्री-लेवल 2-व्हीलर की प्राइस 40% तक बढ़ी है। इस कारण टियर-2 व टियर-3 शहरों के Budget-Concious बॉयर्स द्वारा नया व्हीकल खरीदने की योजनाओं को टाला जाने लगा है।

हीरो मोटोकॉर्प की फिलिपीन में उतरने की तैयारी, टेराफिरमा मोटर्स से हाथ मिलाया

नयी दिल्ली/एजेंसी। टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प फिलिपीन के बाजार में उतरने जा रही है। कंपनी ने कहा कि फिलिपीन में अपने वाहनों की असेंबलिंग और वितरण के लिए उसने टेराफिरमा मोटर्स कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है। एक नियामकीय सूचना में कहा, कोलंबियन ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकाई टेराफिरमा मोटर्स कॉरपोरेशन (टीएमसी) फिलिपीन में हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिलों को असेंबल करेगी और वह वितरक भी होगी। टीएमसी लगुना शहर में स्थित अपनी मौजूदा प्रमुख विनिर्माण सुविधा में 29,000 वर्ग मीटर की एक असेंबली सुविधा स्थापित करेगी और वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में अपना परिचालन शुरू करेगी।हीरो मोटोकॉर्प के वैश्विक कारोबार प्रमुख संजय भान ने कहा, ''हम हमेशा वैश्विक बाजारों में नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए टेराफिरमा मोटर्स कॉरपोरेशन के साथ हमारी साझेदारी इस विस्तार रणनीति का एक अभिन्न अंग है।'' मौजूदा समय में, हीरो मोटोकॉर्प की एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण और मध्य अमेरिका के 43 देशों में उपस्थिति है। इसके 8 विनिर्माण संयंत्र हैं, जिनमें से 6 भारत में हैं। एक-एक संयंत्र कोलंबिया और बांग्लादेश में हैं।

पुराने टू-व्हीलर्स के खरीद-बिक्री प्लेटफार्म बीपकार्ट ने 90 लाख डॉलर जुटाए

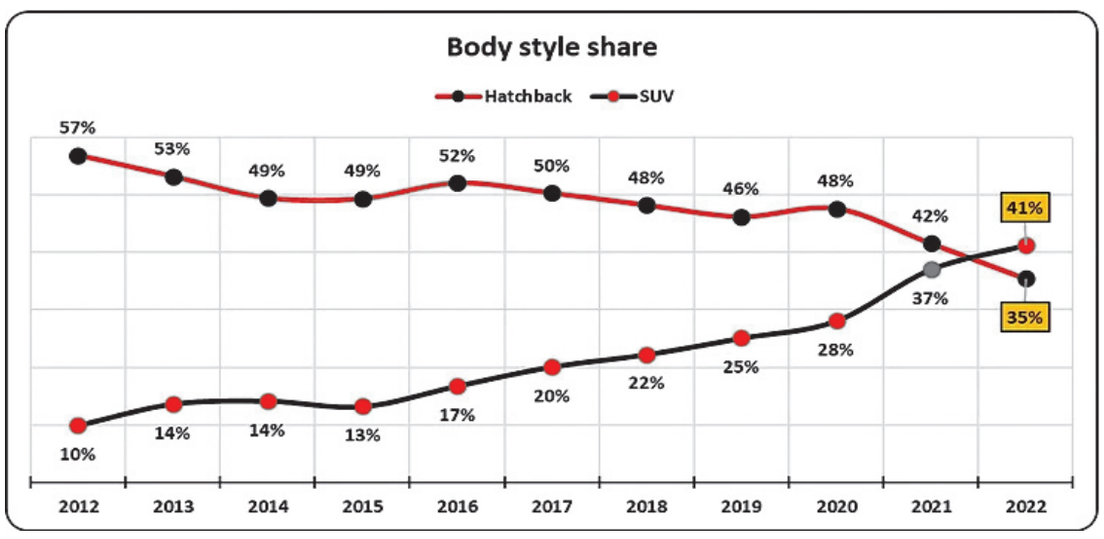
मुंबई/एजेंसी। पुराने दो पहिया वाहनों की खरीद-बिक्री का ऑनलाइन मंच 'बीपकार्ट' ने वरटेक्स वेंचर्स की अगुवाई में 90 लाख डॉलर का कोष जुटाया है। वित्त पोषण के श्रृंखला-ए दौर में मौजूदा निवेशक स्टेलारिस वेंचर पार्टनर्स और चिराटे वेंचर्स भी शामिल हुए। स्टेलारिस ने एक बयान में कहा कि स्टेलारिस और चिराटे वेंचर्स ने सितंबर 2021 में बेंगलुरु स्थित इस स्टार्टअप के लिए 30 लाख डॉलर जुटाए थे। हेमिर दोशी और अभिषेक सर्राफ की अगुवाई वाली बीपकार्ट 2021 में बनी थी। यह पुराने दोपहिया वाहनों के विक्रेता और खरीदारों को एक मंच पर लाती है। उद्योग की रिपोर्ट के मुताबिक पुराने दोपहिया वाहनों का बाजार करीब 10 अरब डॉलर का है लेकिन इसमें विश्वास, सुविधा की कमी और पैसे के मूल्य को लेकर संशय जैसी कठिनाइयां हैं।

भारत फोर्ज ने लिथियम आयन बैटरी प्रणाली के लिए जनरल एटॉमिक्स के साथ समझौता किया

नयी दिल्ली/एजेंसी। रक्षा क्षेत्र की भारतीय कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड ने कहा कि उसने लिथियम आयन बैटरी प्रणाली विकसित करने में मदद के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ एक समझौता किया है। इस बैटरी प्रणाली का उपयोग भारतीय नौसेना करेगी। गुजरात के गांधीनगर में रक्षा प्रदर्शन के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सहमति पत्र (एमओयू) की शर्तों के तहत भारत फोर्ज और जनरल एटॉमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स ग्रुप (जीए-ईएमएस) साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए नौसैनिक मंचों में उपयोगी लिथियम आयन बैटरी प्रणाली विकसित करेंगे। भारत फोर्ज ने कहा कि दोनों पक्ष स्थायी मैग्नेट मोटर के क्षेत्र में भागीदारी के लिए भी सहमत हुए हैं। पनडुब्बियों सहित विभिन्न नौसैनिक मंचों में लिथियम आयन बैटरी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। कल्याणी समूह के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने कहा, हम रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में विशिष्ट प्रौद्योगिकी लाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। भारत फोर्ज लिमिटेड कल्याणी समूह का हिस्सा है।

जनवरी-सितंबर 2022 में हैचबैक व एसयूवी कारों का कुल कार सेल्स में शेयर

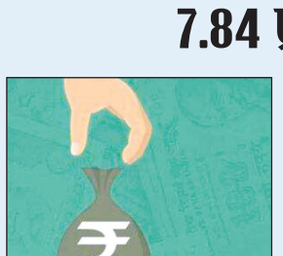




आधार के माध्यम से सितंबर माह में 25.25 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन

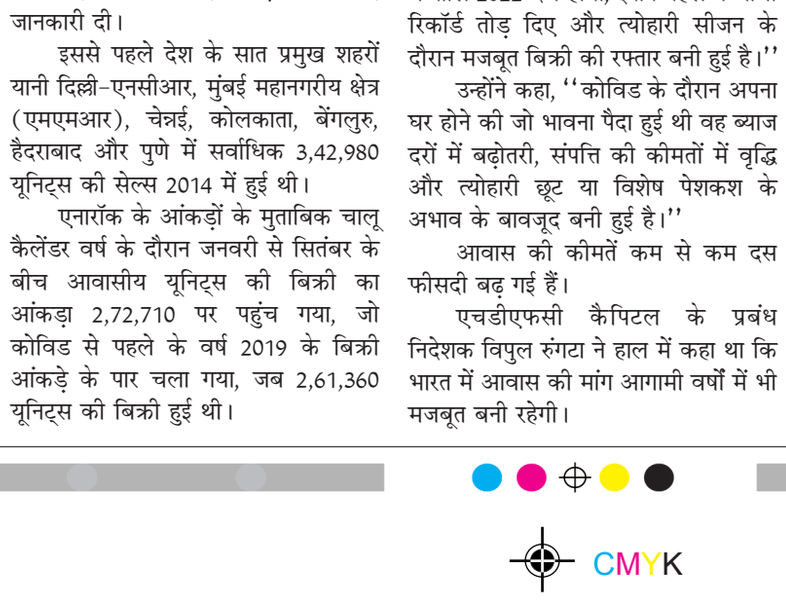
नयी दिल्ली/एजेंसी। देश में सितंबर में आधार के माध्यम से 25.25 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन हुए है। यह संख्या अगस्त की तुलना में 7.7 प्रतिशत अधिक है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। एक ई-केवाईसी लेनदेन केवल आधार धारक की स्पष्ट सहमति से पूरा किया जाता है, जो कागजी कार्रवाई और केवाईसी के लिए व्यक्तिगत सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करता है। बयान में कहा गया, ''सितंबर में 25.25 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन आधार के माध्यम से किए गए, जो अगस्त की तुलना में लगभग 7.7 प्रतिशत ज्यादा है।'' इसी के साथ आधार के माध्यम से अब तक ई-केवाईसी लेनदेन की कुल संख्या सितंबर, 2022 के अंत तक बढ़कर 1,297.93 करोड़ हो गई है। इसी तरह, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) वित्तीय समावेश में सहायक रही है। बयान के अनुसार, ''कुल मिलाकर सितंबर, 2022 के अंत तक एईपीएस और सूक्ष्म एटीएम नेटवर्क के माध्यम से अंतिम छोर तक 1,549.84 करोड़ बैंकिंग लेनदेन संभव किये गए हैं। केवल सितंबर में पूरे भारत में 21.03 करोड़ एईपीएस लेनदेन किए गए।'' सितंबर में आधार के जरिये 175.41 करोड़ सत्यापित लेनदेन किए गए।

राज्यों के कर्ज की लागत 0.12 प्रतिशत बढ़कर 7.84 प्रतिशत



मुंबई/एजेंसी। राज्यों के लिये बाजार से कर्ज जुटाने की औसत लागत ताजा नीलामी में 0.12 प्रतिशत बढ़कर 7.84 प्रतिशत पर पहुंच गई है। केंद्र के लिए यह स्थिर रही है। लगातार चार सप्ताह तक बढ़ने के बाद 18 अक्टूबर को हुई नीलामी में राज्यों के कर्ज की लागत 0.11 प्रतिशत घटकर 7.72 प्रतिशत रह गई थी। इक्रा रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि कर्ज की भारांश औसत लागत (कट ऑफ) 0.12 प्रतिशत बढ़कर 7.84 प्रतिशत हो गयी जो पिछली नीलामी में 7.72 प्रतिशत थी। भारांश औसत अवधि 12 साल से बढ़कर 13 साल होने से कर्ज लागत बढ़ी है। बॉन्ड की ताजा नीलामी में 14 राज्यों ने 25,200 करोड़ रुपये जुटाए जो इस सप्ताह के लिये निर्धारित राशि (24,500 करोड़ रुपये) से तीन प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी सबसे बड़ी नीलामी थी। कुल मिलाकर 24 राज्यों ने 3.5 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं जो एक साल पहले के स्तर की तुलना में छह प्रतिशत कम है।

इस वर्ष 7 प्रमुख शहरों में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकती है Home Sales



नयी दिल्ली/एजेंसी

आवास ऋण पर ब्याज दरें बढ़ने और संपत्ति की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने के बावजूद आवास की मांग सभी मूल्य श्रेणियों में मजबूत बनी हुई है और देश के सात प्रमुख शहरों में इस साल आवास बिक्री 3.6 लाख यूनिट्स के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। संपत्ति सलाहकार एनारॉक ने यह जानकारी दी।

इससे पहले देश के सात प्रमुख शहरों यानी दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर), चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में सर्वाधिक 3,42,980 यूनिट्स की सेल्स 2014 में हुई थी।

एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान जनवरी से सितंबर के बीच आवासीय यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा 2,72,710 पर पहुंच गया, जो कोविड से पहले के वर्ष 2019 के बिक्री आंकड़े के पार चला गया, जब 2,61,360 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

इस वर्ष बिक्री आंकड़ा 3.6 लाख यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान जताते हुए संपत्ति परामर्शदाता ने कहा कि आवास ऋण पर ब्याज दर 6.5 फीसदी से बढ़कर करीब 8.5 फीसदी हो जाने पर भी आवास की मांग त्योहारों के दौरान मजबूत बनी रही है।

एनारॉक समूह के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, ''भारत में आवास बाजार के इतिहास में साल 2022 दर्ज होगा, इसने पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और त्योहारी सीजन के दौरान मजबूत बिक्री की रफ्तार बनी हुई है।''

उन्होंने कहा, ''कोविड के दौरान अपना घर होने की जो भावना पैदा हुई थी वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी, संपत्ति की कीमतों में वृद्धि और त्योहारी छूट या विशेष पेशकश के अभाव के बावजूद बनी हुई है।''

आवास की कीमतें कम से कम दस फीसदी बढ़ गई हैं।

एचडीएफसी कैपिटल के प्रबंध निदेशक विपुल रुंगटा ने हाल में कहा था कि भारत में आवास की मांग आगामी वर्षों में भी मजबूत बनी रहेगी।



Nandani Creation Ltd नंदनी क्रिएशन लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस - जी-13, करतारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, 22 गोदाम के पास, जयपुर - 302006
CIN: L1801RJ2012PLC037976 Web-site : www.nandanicreation.com,
E-mail: info@jaipurkurti.com, cs@jaipurkurti.com Phone: 0141-4037596

30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक के लिए अनअंकेक्षित स्टेंडअलोन व समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(रुपये लाख में, शेयर व प्रति शेयर डाटा के अलावा)

क्र. सं.	विवरण	स्टेंडअलोन					
		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2022 (अनअंकेक्षित)	30.06.2022 (अनअंकेक्षित)	30.09.2021 (अनअंकेक्षित)	30.09.2022 (अनअंकेक्षित)	30.09.2021 (अनअंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	1258.38	1319.71	1571.79	2578.09	2960.05	5551.02
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं से पूर्व)	25.81	56.36	129.91	82.17	249.09	21.59
3.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	25.81	56.36	129.91	82.17	249.09	21.59
4.	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	17.52	38.64	105.06	56.16	189.71	10.20
5.	अवधि के लिए कॉम्प्रीहेंसिव कुल आय	17.61	38.49	105.04	56.10	189.76	10.69
6.	चुकता अंश पूंजी (रुपये 10 प्रति शेयर अंकित मूल्य)	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39
7.	प्रति शेयर आय : (रुपये 10 प्रति शेयर अंकित मूल्य) मूल: एवं घूलित (तिमाहियों के लिए वार्षिक नहीं)	0.18 -	0.38 -	1.05 -	0.56 -	1.89 -	0.11 -

(रुपये लाख में, शेयर व प्रति शेयर डाटा के अलावा)

क्र. सं.	विवरण	समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2022 (अनअंकेक्षित)	30.06.2022 (अनअंकेक्षित)	30.09.2021 (अनअंकेक्षित)	30.09.2022 (अनअंकेक्षित)	30.09.2021 (अनअंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	1434.97	1466.09	1754.75	2901.06	3138.27	6335.84
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं से पूर्व)	37.07	56.92	155.48	93.99	292.48	68.33
3.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	37.07	56.92	155.48	93.99	292.48	68.33
4.	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	27.64	38.74	124.96	66.38	224.01	49.58
5.	अवधि के लिए कॉम्प्रीहेंसिव कुल आय	27.91	38.74	124.94	66.65	224.06	50.18
6.	चुकता अंश पूंजी (रुपये 10 प्रति शेयर अंकित मूल्य)	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39
7.	प्रति शेयर आय : (रुपये 10 प्रति शेयर अंकित मूल्य) मूल: एवं घूलित (तिमाहियों के लिए वार्षिक नहीं)	0.28 -	0.39 -	1.25 -	0.66 -	2.23 -	0.49 -

नोट : (ए) उक्त वित्तीय परिणाम 25 अक्टूबर 2022 को आयोजित बैठक में ऑडिट कमिटी द्वारा रिव्यू करने के साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मंजूर किए गए हैं। (बी) उपरोक्त जानकारी 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक के लिए अनअंकेक्षित स्टेंडअलोन व समेकित वित्तीय परिणामों का ब्योरेवार वित्तीय परिणामों से उद्धत की गयी है जो कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्स्चेंज में दाखिल की गयी है। इन वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्स्चेंज की वेबसाईट www.nseindia.com तथा कंपनी की वेबसाईट www.nandanicreation.com पर उपलब्ध है।

नंदनी क्रिएशन लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर
अनुज मूंदड़ा
चेयरमेन एवं प्रबंध निदेशक
DIN : 05202504

स्थान: जयपुर
दिनांक : 25.10.2022

Economy

THURSDAY, OCTOBER 27, 2022



EFFICIENT USE OF SPECTRUM
K. Rajaraman, telecom secretary

"Technologies evolve continuously, therefore, the use of spectrum also needs to evolve...to give ways to effective and more productive ways of deployment of spectrum

QUICK VIEW



No anti-dumping duty on Chinese pharma chemical

INDIA WILL NOT impose anti-dumping duty on a Chinese chemical used in pharma industry as the finance ministry has not accepted the recommendations of DGTR for imposing the levy. The commerce ministry's investigation arm DGTR had conducted a probe into the alleged dumping and in August it recommended the imposition of the duty.

Identify sensitive posts, CVC tells govt units

THE CENTRAL VIGILANCE Commission has asked public sector banks and central government departments to regularly identify sensitive posts and ensure the rotation of officers manning them within the prescribed time limit.

Isro to expand navigation system

ISRO PLANS TO expand its regional satellite navigation system NaVIC in a bid to increase its use in the civilian sector and also by ships and aircraft travelling far from the country's borders.

Petition to increase anti-graft courts

THE SUPREME COURT is scheduled to hear on October 31 a plea seeking to establish special anti-graft courts in every district to decide cases of economic offences.

SPECIAL FOCUS ON EDUCATION AND HEALTH

FM asks AIIB to invest more in clean energy, social infra

Says Indian economy remains resilient due to reforms

FE BUREAU
New Delhi, October 26

FINANCE MINISTER NIRMALA Sitharaman on Wednesday exhorted the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) to scale up investments in clean energy and social infrastructure, with a special focus on education, health and digital infrastructure. Such a targeted approach, she said, would ensure resources are not scattered across multiple areas and impact remains meaningful.

Speaking at the 7th annual meeting of the Board of Governors of the AIIB through video conference, Sitharaman also asserted that India's "well-targeted policy mix, accompanied by major structural reforms and sound external balance sheet", have aided its growth to remain resilient, despite exogenous threats, according to a finance ministry statement.

The economy, she asserted, has remained resilient and made remarkable progress through its digitalisation mission, harnessing the power of technology to facilitate social protection and boost financial inclusion.



Finance minister Nirmala Sitharaman attends the 7th annual meeting of board of governors of Asian Infrastructure Investment Bank through video conference from New Delhi on Wednesday. PTI

The government has announced a raft of measures in the aftermath of the pandemic--including the launch of a dozen of production-linked incentive schemes, greater thrust on public capex and guaranteed loans to MSMEs and other businesses--to stimulate growth.

Despite a slowdown in its growth this fiscal, India will remain the world's fastest-growing economy. The International Monetary Fund has forecast its FY23 growth for the country at 6.8%, more than double the expected global economic expansion rate for 2022.

The finance minister asked the AIIB to not only play a "catalytic role in mobilizing diverse private sector resources but also explore mechanisms to augment its own resources", pointing out that public resources are insufficient to meet vast infrastructure needs of members. The AIIB could focus on early action on the recommendations of G20 Expert Panel's Report on the capital adequacy framework of multilateral development banks.

Since its inception in 2016, the AIIB has approved a total financing of $36.44 billion. As many as 191 projects have been cleared by it since 2016, with 50 in 2021 and 33 so far this year.

About 23% of the approved projects belong to the energy sector, followed by transport (16%). Highlighting India's commitment to the environmental cause, Sitharaman stated that Prime Minister Narendra Modi himself is leading the country's climate change response through various programmes, including 'Lifestyle for Environment', or LiFE.

Beyond its financial assistance, the AIIB should work towards expanding the scope of its midstream and upstream engagement activities, such as increased technical assistance to help clients translate strategies into investment plans, the finance minister said.

India, a founding member and the second-largest shareholder in AIIB, has the largest project portfolio within the so-called BRICS Bank. New Delhi holds a 7.65% vote share in the AIIB, while China, the largest shareholder, has 26.63% in it.

Give suggestions on telecom bill by Nov 10: Vaishnaw

JATIN GROVER
New Delhi, October 26

COMMUNICATIONS MINISTER ASHWINI Vaishnaw on Wednesday asked the industry to send in their comments on the draft telecom bill latest by November 10.

The comments from the minister come after the department of telecommunications recently extended the deadline for views on the draft telecom bill to October 30 from October 20.

"We have received comments from various industry bodies, we can extend the deadline by another 10 days if needed. So, I urge the industry to share reforms before November 10, so that we can take the bill to parliament at the earliest," communications minister Ashwini Vaishnaw said.

The draft telecom bill focuses on removing certain fee and penalties for the telecom sector by replacing it with the traditional reforms governing the sector.

Through the bill, the government has also proposed to extend the definition of telecommunications to include over-the-top (OTT) communication services, machine-to-machine communication services, internet and broadband communication service providers, among others.

The government aims to implement the telecom bill in the next 6-10 months, the minister had said last month.

Post finalization of the telecom bill, the government will undertake the much-awaited licensing reforms for the telecom sector, which could reduce certain levies and simplify the licensing provisions for the service providers.

In a bid to expedite the coverage of 5G in the country, Vaishnaw has also urged the telecom service providers to increase the 5G enabled base transceiver stations or BTS to 10,000 per week from 2,500 towers per week at present.

"We have brought a lot of changes for the sector and doing everything that is needed to be done, now the industry should come up and increase the BTS to 10,000 per week," the minister said.

In order to optimize the use of street furniture, the government has also removed the current process for SACFA clearance for 5G antennas on any street furniture.



"We can extend the deadline by another 10 days if needed. So, I urge the industry to share reforms before November 10, so that we can take the bill to parliament at the earliest"

ASHWINI VAISHNAW, COMMUNICATIONS MINISTER

The government today detailed the procedural reforms it took in the telecom licensing and satellite communications. The purpose of the reforms is to promote ease of doing business for the sector and enable last mile connectivity of internet services in the country.

"This is part of the series of reforms that the government is doing, we would want the world to copy India's laws," Vaishnaw said. Among key reforms for wireless licensing, the government has simplified the telecom tower clearance process, delicensed some frequency bands for devices such as Wi-Fi routers, Bluetooth etc.

"1Mhz additional spectrum in 867-868 MHz and revised regulations in 433 MHz band will help in better equipment availability. The bands are useful for IoT devices," the government said.

In the satellite communication space, the government has introduced self certification in antenna deployment.

India-China trade crosses $100 bn in Jan-Sept

India's trade deficit climbs to over $75 bn during the period

PRESS TRUST OF INDIA
Beijing, October 26

INDIA AND CHINA bilateral trade continued to boom, crossing $100 billion for the second year in the first nine months of 2022 while India's trade deficit climbed to over $75 billion, according to trade data released by Chinese customs.

The total bilateral trade, amidst the military standoff in eastern Ladakh, went up to $103.63 billion, registering a 14.6% increase compared to last year during the same period.



China's exports to India climbed to $89.66 billion, registering an increase of 31%, data released by China's General Administration of Customs (GAC) said.

However, India's exports in the past nine months stood at $13.97 billion, registering a decline of 36.4%.

As a result, the total trade deficit went up to over $75.69 billion.

Last year, the India-China bilateral trade hit a record high of over $125 billion crossing the $100 billion mark in a year when the relations touched a new low due to the standoff by the militaries in eastern Ladakh. Last year, China's exports to India went up by 46.2 per cent to $97.52 billion while India's exports to China grew by 34.2 per cent to $28.14 billion.

The trade deficit for India stood at $69.38 billion in 2021.

Nandani Creation Ltd NANDANI CREATION LIMITED

Regd. Office: G-13, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam, Jaipur-302006
CIN: L18101RJ2012PLC037976
Web-site: www.nandanicreation.com , **e-mail:** info@jaipurkurti.com, cs@jaipurkurti.com **Phone:** 0141-4037596

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

(Figures in Lacs except EPS)

Sr. No.	PARTICULARS	Standalone					
		QUARTER ENDED			HALF YEAR ENDED		YEAR ENDED
		30.09.2022 (UNAUDITED)	30.06.2022 (UNAUDITED)	30.09.2021 (UNAUDITED)	30.09.2022 (UNAUDITED)	30.09.2021 (UNAUDITED)	31.03.2022 (AUDITED)
1.	Total Income from Operations	1258.38	1319.71	1571.79	2578.09	2960.05	5551.02
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	25.81	56.36	129.91	82.17	249.09	21.59
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	25.81	56.36	129.91	82.17	249.09	21.59
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	17.52	38.64	105.06	56.16	189.71	10.20
5.	Total Comprehensive Income for the period	17.61	38.49	105.04	56.10	189.76	10.69
6.	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs. 10 each)	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39
7.	Earnings per Share (Face Value of Rs. 10/- each) Basic & Diluted (not annualized for quarters)	0.18	0.38	1.05	0.56	1.89	0.11

Sr. No.	PARTICULARS	Consolidated					
		QUARTER ENDED			HALF YEAR ENDED		YEAR ENDED
		30.09.2022 (UNAUDITED)	30.06.2022 (UNAUDITED)	30.09.2021 (UNAUDITED)	30.09.2022 (UNAUDITED)	30.09.2021 (UNAUDITED)	31.03.2022 (AUDITED)
1.	Total Income from Operations	1434.97	1466.09	1754.75	2901.06	3138.27	6335.84
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	37.07	56.92	155.48	93.99	292.48	68.33
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	37.07	56.92	155.48	93.99	292.48	68.33
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	27.64	38.74	124.96	66.38	224.01	49.58
5.	Total Comprehensive Income for the period	27.91	38.74	124.94	66.65	224.06	50.18
6.	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs. 10 each)	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39
7.	Earnings per Share (Face Value of Rs. 10/- each) Basic & Diluted (not annualized for quarters)	0.28	0.39	1.25	0.66	2.23	0.49

NOTES:
A) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 25th October, 2022 and have been subject to Limited review by the Statutory Auditors of the Company. The Statutory Auditors have expressed an unmodified review opinion on these results . B) The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter & Half year ended 30th September, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full Format of the statement of Standalone Financial Results are available on the Company's website **(www.nandanicreation.com)** and on the website of the National Stock Exchange of India limited **(www.nseindia.com).**

FOR NANDANI CREATION LIMITED
Sd/-
ANUJ MUNDHRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DIN: 05202504

DATE: 25.10 .2022
PLACE: JAIPUR

Govt working to ensure efficient use of spectrum

FE BUREAU
New Delhi, October 26

THE GOVERNMENT IS working with all sectors to ensure efficient use of spectrum for convergence of emerging technologies, telecom secretary K. Rajaraman said today.

"(As) technologies evolve continuously, therefore, the use of spectrum also needs to evolve...to give ways to effective and more productive ways of deployment of spectrum," he said at the India Space Congress 2022.

Spectrum refers to the radio frequencies allocated to telecom service providers and other sectors to facilitate communication over the airwaves for providing internet, voice services, among other communication services.

Comments from the telecom secretary assume significance in light of the different views from the satellite operators and telecom industry for the satellite spectrum. While the telecom companies want the spectrum for satellite communication services to be auctioned, the satellite services providers want the government to allot spectrum administratively.

Companies such as Bharti Group-backed One Web, Jio Satellite Communications, among some global players, are currently in the race to offer satellite-broadband services in the country.

While the department of telecommunications has pitched for auctioning of airwaves, the TRAI is yet to come up with its recommendations on the method of allocation of spectrum. Through effective deployment of spectrum, the government also aims to ensure convergence of emerging technologies. For example - compatibility of devices such as smartphones to support both terrestrial networks as well as satellite communication services.

FROM THE FRONT PAGE

Pre-IPO shares worth ₹12,000 cr could hit market by year end

Market watchers point out that demand for shares of new-age technology stocks could increase if the prices fall further and valuations turn attractive. "Even the promoters may turn buyers if the prices of their companies fall sharply," said Kalyaniwala.

For issues opening from April this year, the lock-in period for all categories of pre-IPO investors has been reduced to six months from the date of their acquisition. Earlier, the lock-in for pre-IPO investors was one year. For the promoters, up to 20% of the post-issue paid-up capital must be locked in for 18 months; earlier this was three years The lock-in requirement for allotment exceeding 20% of the post-issue paid-up capital has been reduced to 6 months. The lock-in provision for anchor investors is that 50% of shares allotted to them is locked in for 30 days and the remaining 50% is locked in for 90 days.

Evaluating next steps: Google on CCI orders

"The CCI's decision is a major setback for Indian consumers and businesses, opening serious security risks for Indians who trust Android's security features, and raising the cost of mobile devices for Indians," a Google spokesperson said, adding that the company will review the decision to evaluate next steps.

Appeals against CCI orders can be filed in the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT).

India is among the biggest markets of Google for its Play Store services and Android.

Housing sales may surpass 2014 high

Housing sales have remained strong despite average property prices increasing in 2022, with the annual price appreciation in Q3 2022 being the most in the past seven years – 6% against Q3 2021.

Anuj Puri, chairman, Anarock Group, said, "The year 2022 will create residential market history in India, having already breached all previous highs and continuing to witness strong sales momentum in the ongoing festive season. Home-ownership sentiment retained the vibrancy ushered in by the Covid-19 era – despite interest rates hikes of 190 basis points, increased property rates and the conspicuous lack of festive season offers and discounts this year."

However, total new launches in 2022 will remain lower than the previous peak of 2014, which saw around 545,000 homes launched across the top seven cities. Current trends indicate that launches in these cities will exceed 340,000 units in the whole of 2022, according to Anarock.

Kanorias dismiss administrator's claim on fraud

Srei sources say that BDO is a consulting firm with no audit experience and is not even registered with the Auditors Association (AASB) and NFRA (National Financial Reporting Authority).

In addition, they say that out of the four loans in question, two were given in the routine course of business interest rates ranging around 12-13%. Hence, there was no question of fraud.

Further, these loans were paid back on time. And the administrator has recalled two wrongly tagged fraud loans that they were unable to comprehend the complexities of infra financing.

Sources close to the matter told FE that the administrator has received the letter from Kanoria. "As per the report of transaction auditor BDO, the administrator has filed some cases before the Kolkata bench of the NCLT under Section 66 (IBC). Then the erstwhile management has reacted on it," said the sources.

The auditor named both the promoters – Hemant Kanoria and Sunil Kanoria – for their involvement in these transactions apart from the 'beneficiary' firms. The biggest transaction involving ₹838 crore was loan disbursement to Aviral Maritime Infrastructure Dahej Private and Adinath Port and Logistics.

Refuting the charge, Kanoria's letter says: "Since the report of said transactional auditor, namely BDO, is yet to be validated by the tribunal, your act of intimating/informing/disclosing any information which is pending adjucation could not have been made by you as the same is not permissible by the provisions of the Code."

The letter added: "You are espousing a personal vendetta and your allegations made against the parties is meritless."

Kanoria's letter also said that if the report is not withdrawn immediately, the promoters will take appropriate action advised by law.

Insolvency proceedings against Srei Infrastructure Finance (SIFL) and its subsidiary Srei Equipment Finance (SEFL) commenced from October 2021 after the insolvency petitions, filed by the RBI, had been approved by the NCLT Kolkata bench.

Sharma, former CGM of Bank of Baroda, took charge of the two Srei companies after the central bank had come down heavily on both the companies over governance issues and superseded the boards of directors.